

इंदौर, हरदा, डडौरी और सागर में खुलेंगी साइबर तहसील

चर्चा में क्यों?

9 अक्टूबर, 2022 को मध्य प्रदेश के राजस्व एवं परविहन मंत्री गोवदि सहि राजपूत ने बताया कि सीहोर एवं दतिया ज़िले से साइबर तहसीलें बनाने के पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद इस नवाचार की योजना के द्वितीय चरण को इंदौर, हरदा, डडौरी और सागर में भी लागू किया जा रहा है।

प्रमुख बंदि

- राजस्व एवं परविहन मंत्री ने बताया कि साइबर तहसील लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का इकलौता राज्य है, जसिने इस अभनलव प्रयोग के ज़रयल लंबतल राजस्व प्रकरणों के नरलकरण में आशातीत सफलता पाई है।
- मंत्री गोवदल सहल राजपूत ने कहा कि द्वलतीय पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद इसे पूरे राज्य में लागू करने की योजना बनायी जा रही है। उन्होंने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के सेकेंड फेज की सफलता का आकलन करने के लयल 6 महीने तक इसके परणलम का अधययन कयल जाणगा और फरल इसे पूरे राज्य में लागू कयल जाणगा।
- वदलतल है कि अववलदतल नामांतरण/बैंटवारे के प्रकरणों को सरलता से नपलटाने के लयल साइबर तहसील का गठन कयल गया थल।
- जसल ज़ललें में साइबर तहसील कार्य करेगी, उस ज़ललें के लोगों को अववलदतल नामांतरण/बैंटवारे के प्रकरणों के लयल तहसील कार्यालय जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ऑनलाइन आवेदन करके ऐसे अववलदतल नामांतरण/बैंटवारे के प्रकरणों का नरलकरण हो सकेगा।